

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 05 जनवरी, 2010

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत झलमहादेव गढ़ड़ी गंधरे में झूला पुल एवं रिखणीखाल में नयार नदी पर नाछ देवखर में झूला पुल कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (ग.क्ष.) लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के पत्र सं0-264/36(583)याता0-पर्य/07 दिनांक 29.01.2009 एवं संख्या-2730/36(591)याता0-पर्य/08 दिनांक 24.07.2009 एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडाऊन का पत्र सं0-4462/16 सी. 4463/16 सी दिनांक 24.10.2009 के संदर्भ में उपलब्ध कराये गये प्रश्नगत कार्यों का पुनरीक्षित आगमनों के संदर्भ में एवं शासनादेश सं0-2755/111-2/06-52(प्र0आ0)/06 दिनांक 10 नवम्बर, 2006 के क्रमांक सं0-3 एवं 4 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता (ग.क्ष.) लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल में झलमहादेव गढ़ड़ी गंधरे में 50 मी० झूला पुल लागत रु० 97.50 लाख के पुनरीक्षित आगमन पर टी०ए०सी० वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रु० 96.20 लाख (रु० छियासठ लाख बीस हजार मात्र) एवं रिखणीखाल में नयार नदी पर नाछ देवखर में 80 मी० झूला पुल का निर्माण (म०मु०घो०) के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया पुनरीक्षित आगमन लागत रु० 155.50 लाख पर टी०ए०सी० वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रूपये 154.52 लाख (रु० एक करोड़ चौवन लाख बावन हजार मात्र) के पुनरीक्षित आगमन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि शासनादेश सं0-2755/111-2/06-52 (प्र0आ0)/06 दिनांक 10 नवम्बर, 2006 के द्वारा क्रमांक सं0-2 एवं 3 पर प्रश्नगत कार्यों हेतु प्रदान की गई स्वीकृति रूपये 60.75 लाख की धनराशि को घटाते हुए झलमहादेव गढ़ड़ी गंधरे में 50 मी० झूला पुल हेतु रु० 35.45 लाख (रु० पैंतीस लाख पैंतालीस हजार मात्र) एवं क्रमांक सं0-3 पर रिखणीखाल में नयार नदी पर नाछ देवखर में 80 मी० झूला पुल कार्य की पूर्व स्वीकृत धनराशि रु० 99.12 लाख की धनराशि को कम करते हुए रु० 55.40 लाख (रु० पचपन लाख चालीस हजार मात्र) की पुनरीक्षित वृद्धि में इन कार्यों को पूर्ण करा लिया जायेगा तथा अब इसके लिए कोई भी अतिरिक्त वृद्धि किन्हीं भी कारणों से देय नहीं होगी। उक्त शासनादेश केवल उक्त अनुमन्त्र सीमा तक ही संशोधित सम्झा जाय। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि आवंटन के बाद व्यय कर दी गई हो तो उस धनराशि को समायोजित करके अवशेष धनराशि ही बचत कार्यों पर अवमुक्त की जायेगी।

3. उत्तराखण्ड प्रोजेक्ट नियमावली 2008 में उल्लिखित अनुदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं भिजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम बरियता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
6. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
7. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के माध्यम नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
9. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भौति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
10. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
11. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
12. यदि उक्त कार्य में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
13. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त विवरण प्रस्तुत किये जाने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।
14. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
15. उक्त योजना पर व्यय राज्य सेक्टर के अन्तर्गत (मार्ग के चालू कार्य) के निर्वहन पर रखी गई धनराशि से आवश्यकतानुसार अपने स्तर से ही किया जाये।
16. यह आदेश लोक निर्माण विभाग की पत्रावली संख्या-52 (प्रौ0आ0)/06 एवं सं0-07(प्रौ0आ0)/05 टी0सी0-01 में प्राप्ता वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)

उप सचिव।

[हस्ताक्षर]

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबराय मोटर्स मजरा, देहरादून ।
 - 2- आयुक्त गढ़वाल मंडल, पीड़ी ।
 - 3- जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, पीड़ी ।
 - 4- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो० नि० वि०, पीड़ी ।
 - 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
 - 6- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन ।
 - 7- बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड शासन ।
 - 8- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडाऊन ।
 - 9- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून ।
 - 10- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक

जाज्ञा से,
[Signature]
(महिमा)
अनु सचिव ।